

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF FINANCE
DEPARTMENT OF EXPENDITURE

RAJYA SABHA
UNSTARRED QUESTION No. 395
TO BE ANSWERED ON TUESDAY, FEBRUARY 6, 2024/ 17 MAGHA, 1945 (SAKA)

INFORMATION REGARDING EIGHTH PAY COMMISSION

395 SHRI RAM NATH THAKUR:

Will the Minister of *Finance* be pleased to state:

- (a) the reasons recorded on files for not considering and according approval of Para 1.22 of 7th CPC by Government;
- (b) whether no proposal for setting up Eighth Central Pay Commission is under consideration due to the fact that Government is not in a position to bear the burden of pay commission;
- (c) if so, the details and reasons for such situation; and
- (d) if not, the reasons why 5th largest economy is not setting up Eighth Central Pay Commission and revising pay of the Central Government employees who are facing unprecedented inflation in the last thirty years?

ANSWER
MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE
(SHRI PANKAJ CHAUDHARY)

(a): This issue has not been considered by the Union Cabinet while according the approval for the revision of pay and allowances based on 7th CPC.

(b) to (d): No such proposal is under consideration of the Government.

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

राज्य सभा

लिखित प्रश्न संख्या - 395

मंगलवार, 06 फरवरी, 2024/ 17 माघ, 1945 (शक) को उत्तर दिए जाने के लिए

आठवें वेतन आयोग संबंधी जानकारी

395 श्री राम नाथ ठाकुर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) सरकार द्वारा सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग के पैरा 1.22 पर विचार न करने और उसे अनुमोदित न किए जाने के फाइलों में दर्ज कारण क्या हैं;
- (ख) क्या इस तथ्य के कारण कि सरकार वेतन आयोग संबंधी खर्च वहन करने की स्थिति में नहीं है, आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग के गठन का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी स्थिति के क्या कारण हैं; और
- (घ) यदि नहीं, तो पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था द्वारा आठवें केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन न किए जाने और विगत तीस वर्षों से अभूतपूर्व मुद्रास्फीति का सामना कर रहे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन न किए जाने के क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

- (क) : सातवें वेतन आयोग के आधार पर वेतन और भत्तों में संशोधन को अनुमोदन देते समय केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने इस मामले पर विचार नहीं किया है।
- (ख) से (घ) : सरकार के पास इस प्रकार का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
